vestigated and it is in the final stages, where on account of a broken piece of the wind-screen the matter came to light. Mr. Chopra's case is being investigated. Why not wait till the result of the investigation is known? Within a few hours after an offence is committed, you come out with some story which wil give a different impression to the public. The humble request I want to make to hon. Members is that in matters where a crime is involved, allow some time and wait till the investigations are completed. Something has been said about hand-grenades.

श्री जनेश्वर मिश्र (इलाहाबाद) : कील निकाल कर कागज में लपेटी गई थी—ये इस बात को कबूल करते है, उस के बाद भी कहते है कि सीरियस बम था।

SHRI K. BRAHMANANDA REDDY: Live handgrenades were thrown, but providentially the fuse of the detonator did not ignite. It was a providential escape.

श्री जनेश्वर मिश्र : आप ने जूडीशियरी को टेरोराइज करने के लिए ऐसा किया है—यह हम लोगो का आप पर चार्ज है।

SHRI K. BRAHMANANDA REDDY: Some conclusions were attempted to be drawn from the fact that two detonators were thrown and none of them exploded; therefore, they were planted there.

श्री जनेश्वर मिश्र : मीसा को कन्टीन्यु कराने के लिए, जूडीशियरी को टेरोराइज करने के लिए इन लोगों ने ऐसा किया है।

SHRI K. BRAHMANANDA REDDY: I am not very much surprised at the sudden ejaculations of my friend Shri Janeswar Mishra.

AN HON. MEMBER: Ajnaneswar.

SHRI K. BRAHMANANDA REDDY: I do not want to say that.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Ejaculations too!

SHRI K. BRAHMANANDA REDDY: So far as Samastipur incident is concerned, it was a difficult job. The CBI have undertaken a very difficult task. I hope they are in the final stages of their investigation and probably they will take further steps to put the matter before a court of law. Even about this attack on the Chief Justice, police have got some useful clues and they are working on them. I hope ere long it will be possible for the police to book the real culprit.

SHRI S M. BANERJEE: After how many incidents?

SHRI K. BRAHMANANDA REDDY: I welcome your rumour, but there is a place for it So far as the constable is concerned, it is the constable on duty who has been suspended, not an old man who was brought and suspended.

SHRI S M BANERJEE: A man who was not on duty has been suspended.

SHRI K. BRAHMANANDA REDDY: If all of us want this cult of hatred or atmosphere of hatred not to spread in this country leading to sporadic violence or conspiracies, it should be our effort to create more confidence in the functioning of our system and in the fact that we will be able to deliver the goods through this system.

16.30 hrs.

STATUTORY RESOLUTION RE. DISAPPROVAL OF THE PRESS COUNCIL (SECOND AMENDMENT) ORDINANCE 1974 AND PRESS COUNCIL (AMENDMENT) BILL —*contd.*

MR. DEPUTY-SPEAKER: We resume discussion on the Statutory Resolution of Dr. Laxminarayan Pandeya to disapprove the Press Council (Second Amendment) Ordinance and the Bill of Shri Gujral. Dr. Pandeya is to continue his speech.

डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय (मंदसौर). उपाध्यक्ष जी, यह सरकार इस बात की आदी हो गई है कि छोटे से छोटे मामले को ले कर भी अध्यादेश का उपयोग किया जाय। प्रैस परिषद् के मामले में भी सरकार द्वारा यही भूमिका निभाई गई है। यह कोई पहला अवसर नही था जब कि सरकार द्वारा अध्यादेश के जरिए इस की अवधि बढ़ाने की बात कही गई हो।

16 31 hrs

(SHRI VASANT SATHE *in the Chair*)

इसके पहले भी 1973 म, उस के बाद फिर 1974 में और अब तीसरी बार अध्यादेश के जरिए प्रैस परिषद् की अवधि बढाने की बात ले कर सरकार यहा पर आई है। इस बार भी वही कारण दिये गये है जो कि पहली बार और दूसरी बार दिये गये। इस बार भी वही कारण सरकार की तरफ से दिये गये। कोई नई बात नहीं कहा गई। अध्यादेश का इस प्रकार का दुरुपयोग आप बन्द करे। इस के जरिए जो काम चलाने की प्रवृत्ति बढती जा रही है यह ठीक नही है, इस को रोका जाना चाहिए। पहली बार 1973 में यहा पर इस प्रकार का अध्यादेश लाया गया था तब भी यह बात कही गई थी कि हम से इस परिषद के ठीक से गठन के लिए या इस का किस प्रकार का उपयुक्त यत्र हो, इस की खोज के लिए अवधि बढाना चाहते है और दूसरी बार भी यही कहा गया

"ऐसे यत्र के स्थापित किये जाने तक प्रेस परिषद के अध्यक्ष और सदस्यो की पदावधि जो 30 सितम्बर, 1973 को समाप्त हो रही थी, 30 जून, 1974 तक बढाने के लिए पिछले वर्ष प्रेस परिषद अधिनियम का सशोधन किया गया था"। दुबारा भी वही बात की गई और इस अवधि को 28 जून, 1974 के अध्यादेश द्वारा 31 दिसम्बर 1974 तक बढ़ाया गया था। इस के बाद फिर से जब कि सत्र का अंतिम दिन था लोक सभा मे तो सरकार विधेयक प्रस्तुत नही कर सकी लेकिन राज्य सभा मे विधेयक प्रस्तुत करने का प्रयत्न किय और वह भी अंतिम दिन। सरकार इस बात को जानती थी कि 31 दिसम्बर तक यह काम नही हो सकता तो उस की अवधि बढ़ाने मे सबधित बिल पहले ही पास करा लेती। परन्तु ऐसा न कर के 27 दिसम्बर को राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यादेश जारी किया गया जो इस बात का परिचायक है कि सरकार ससद की अवहेलना करना चाहती है यह उस की प्रवृति हो गई है।

16 31 hrs

[SHRI VASANT SATHE *in the Chair*]

जैसा सरकार ने स्वय अपने उद्देश्यो और कारणो मे कहा है कि 'ससद के सदस्यो की प्रैस परिषद् से सम्बन्धित सलाहकार समिति की सिफारिश के अनुसरण मे 1970 मे प्रस परिषद अधिनियम 1965 का सशोधन किया गया था।" और एक प्रक्रिया तय की गई थी कि लोक सभा के अध्यक्ष राज्य सभा के अध्यक्ष और भारत के मख्य न्यायाधीश इस तत्र का गठन करेग और उन्होने गठन भी किया। उस पर कुछ आलोचना और प्रत्यालोचना हुई इस लिए सरकार को फिर से नई प्रक्रिया निर्धारित करने के लिये यहा पर आना पडा। मैं नही समझता इतने बड़े वरिष्ठ पदाधिकारियो पर आलोचना करने का किसी ने प्रयास किया हो। लेकिन जहा तक मेरी जानकारी है किसी एक प्रैस से सबधित यूनियन के कुछ लोगो को लिया गया और दूसरो को नही लिया गया, इस के कारण कुछ मतभेद सामने आये। लेकिन यह नही कहा जा सकता कि किसी दुर्भावन वश किसी एक व्यक्ति को लिया गया और किसी दूसरे को नही लिया गया।

जैसा कि प्रैस काउन्सिल एक्ट की धारा (3) मे कहा गया है

"Thirteen shall be nominated by the Nominating Comittee from among the working journalists o

whom six shall be editors of the papers an dremaining seven shall be working journalists other than editors;"

उस समय आई० एफ० डबलू० ज० के प्रतिनिधियों को बलाया गया नाम देने के लिए लेकिन वह आये नहीं । एन० यू० ज० को प्रतिनिधित्व मिल गया जिस के कारण कुछ विवाद खड़े हुए । लेकिन यह नही कहा जा सकता कि परिषद् ठीक से काम नही कर रही है या परिषद की बातों को ले कर उस के गठन की प्रक्रिया को लेकर के कुछ चर्चा उठायी जाय । इस प्रकार के विवाद ठीक नही हैं । अब मैं कुछ दूसरी बातें उठाना चाहता हूं । जैसा कि प्रस परिषद् के उद्देश्यों और कारणों में बताया गया था :

"The purpose of preserving the freedom of the press and of maintaining and improving the standards of newspapers in India."

लेकिन जहां तक सरकार की नीति का सवाल है सरकार न तो प्रेस की स्वाधीनता के पक्ष में है और न उसके विकास के लिए कोई कदम उठाना चाहती है जिस से प्रेस स्वाधीन हो कर अपना काम करे । कुछ प्रकरण भी एसे सामने आये जब यहा पर बिहार के 'सर्च लाइट' और 'प्रदीप' अखबारो के मामले उठाये गये कि किस प्रकार बिहार सरकार ने उन दोनो को विज्ञापन देने बन्द कर दिये । किस प्रकार हमला हुआ, कार्यालय जलाया, किस प्रकार पंजाब के दो अखबार, जिन में से एक का नाम 'पंजाब केसरी" है उस की बिजली काट देने का काम किया । किस प्रकार हरियाणा सरकार कहती है कि हम प्रेस परिषद के अधिकार क्षेत्र को मानते ही नही । We do not recognise the Press Council even. यदि आप चाहते है कि लोकतंत्र के अन्दर प्रेस स्वाधीनता का कोई महत्व है या जो बकिन्ग जनलिस्ट्स हैं उन का कोई महत्व है या प्रेस देश के अन्दर अपनी भूमिका निभा सके, तो सरकार का नियंत्रण समाप्त होना चाहिये । मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ बर्गीज के प्रकरण में नही जाना चाहता क्यों कि मामला न्यायालय में विचाराधीन है इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीटयूट ने जो कहा है वह मैं आप को बताना चाहता हूं :

"The dismissal of the Editor of the Hindustan Times, Mr B. G. Verghese seems to have been forced on the owners by direct pressure from the Government."

यह मैं नहीं कह रहा यह इटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट की ओर से कहा गया है इस प्रकार का दबाव आया और इसलिये एसा काम करना पडा । इसी प्रकार किसी पेपर का कोटा बढा देना, किसी का घटा देना यह बात भी बराबर हमारे सामने आ रही है । विज्ञापनों के मामले में पिछले दिनो काफी चर्चा आयी कि किसी एक अखबार मे विज्ञापन देना और किसी को बन्द कर देना । यह काम सरकार का ठीक नही कहा जा सकता ।

इस प्रेस परिषद् ने बहुत अच्छे काम भी किए हैं । लेकिन अगर प्रेस परिषद् को ठीक ढग से और काम करने दिया जाता तो अच्छा होता । लेकिन आज सरकार उस को स्वायतता नहीं देती है, और इसी कारण उस के काम करने में कठिनाई पैदा हो रही है । उसकी शक्तियां क्या हैं ? उस के अधिकार में क्या है हरियाणा की सरकार ने उसकी बात नहीं मानी उसे चुप होना पड़ा । आखिर आपने क्या किया ? आप ने एक सलाहकार समिति का निर्माण किया संसद सदस्यो की और वह कोई तंत्र खोजेंगे । उस की अवधि एक बार फ़िर बढ़ायी और अब फ़िर उस की अवधि बढाने जा रहे है अध्यादेश के द्वारा । प्रेस परिषद् द्वितीय संशोधन विधेयक, 1974 जो 21 दिसम्बर, 1974 को राज्य सभा में पेश किया गया था प्रेस परिषद के वर्तमान अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल 31 दिसम्बर, 1974 से 31 दिसम्बर, 1975 तक बढ़ाने का विचार था जब आप को मालूम था पहले ही कि

[डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय]

इस कमेटी का और समय लगेगा जब आप ने 6 महीने की अवधि बढ़ायी थी और पता था कि अपनी सिफ़ारिशों को देने मे इस समिति को और समय लगेगा तो आप को उसी समय ज्यादा अवधि बढानी चाहिये थी। लेकिन उस समय ज्यादा अवधि नही बढायी और अब प्रस्ताव ले कर आये हैं अवधि बढ़ाने का। इससे स्पष्ट है कि प्रेस परिषद् के फक्शन मे किसी न किसी प्रकार से बाधा डालने की कोशिश कर रहे है। प्रेस की मान्यता के प्रति कितनी उदासीनता से विचार किया जाता है यह बडा विचारणीय प्रश्न है। वर्किंग जर्नलिस्टो के वेज बोर्ड के बारे मे 'नव भारत टाइम्स' मे यह निकला है :

> "प्रस्तावित वेतन बोर्ड मे नेशनल यूनियन आफ जर्नलिस्ट को प्रतिनिधित्व न देने के लिये दोनो सदनो मे दोनो पक्षो के सदस्यो ने सरकार की कडी आलोचना की और सरकार ने इस कदम को उक्त यूनियन के साथ अन्याय बताया।"

यह 19 मार्च 1975 के अखबार मे छपा है। एन० यू० ज० के प्रतिनिधि को न लेने का कौनसा कारण है। उसे प्रेस परिषद् की मान्यता है। एक यूनियन को तो मान्यता देना और दूसरी को मान्यता नही देना यह ठीक नही है। इस प्रकार स्वतन्त्रतापूर्वक जो विचारो की अभिव्यक्ति हो सकती है उस को आप अवसर नही देना चाहते। यह साफ जाहिर करता है कि आप निष्पक्ष नही है। अपना अधिकार हर जगह बनाये रखना चाहते है।

मंत्री महोदय ने जैसा कहा, मैं वर्गीस प्रकरण के बारे मे नही कहना चाहता लेकिन सरकार ने जो कुछ किया है सरकार का किस प्रकार से अप्रत्यक्ष हाथ है उस से यह साबित होता है कि मैनेजमेंट के ऊपर किस प्रकार से आप दबाव ला सकते हैं। समाचार-पत्रो मे जो पढ़ने मे आया, बिड़ला ने जो पत्र लिखा है उससे ध्वनि निकलती है कि कुछ मिनिस्टरो का भी इस के अन्दर हाथ है या किसी न किसी मिनिस्टर का उसमें अप्रत्यक्ष हाथ रहा है। यह अप्रत्यक्ष दबाव पड़ा है। मैं जानना चाहता हू कि वह कौन लोग हैं? आज हमारे पत्रो की स्वाधीनता की क्या स्थिति है? प्रेस परिषद पत्रकारो के लिये लाभप्रद सिद्ध हो किस प्रकार उन के हितो का संरक्षण करे यह एक विचारणीय प्रश्न है। मैं समझता हू उस मे बहुत सारी कमिया हैं और सरकार को आगे जा कर प्रेस परिषद् को ऐसा अवसर देना चाहिये जिस से यह ज्यादा सहायक सिद्ध हो सके। इस हेतु सरकार को प्रेस परिषद् को अधिक शक्तिशाली बनाने हेतु प्रभावी पग उठाने चाहिये।

जैसा कि मैंने अभी आप से कहा कि सरकार ने कुछ ऐसी अपनी पद्धति बना रखी है कि सरकार के पक्ष के जो पत्र है, उन को तो सरकार विज्ञापन देती है लेकिन जो पत्र सरकार की भाषा बोलना नही जानते या सरकार की कुछ आलोचना करते है, उन का विज्ञापन देना बन्द कर देती है। ऐसा कई स्टेटो मे देखा गया है। 'स्वदेश' मध्य प्रदेश का अखबार है। उस ने सरकार के विरोध मे कुछ लिखा तो उसे विज्ञापन देना बन्द कर दिया अगर आर्गेनाइजर ने कुछ लिखा तो उस पत्र का सर्कुलेशन बन्द कर दिया। 'मदरलैण्ड' कुछ लिखता है, तो उस का विज्ञापन नही दिया और "पंजाब केसरी" कुछ लिखता है तो उसे विज्ञापन देना बन्द कर दिया। या फिर अखबारी कागज बंद करके अखबार निकालना बन्द कर दिया जाता है।

मै मंत्री जी से एक बात और कहना चाहूगा कि यद्यपि वह इस विषय से सुसंगत हैं किन्तु विधेयक की परिधि मे नही है। मैं जानना चाहता हू कि हिन्दी के विज्ञापनो पर आप कितना खर्च करते हैं और अंग्रेजी के विज्ञापनो पर आप कितना खर्च करते है। यह इस विषय से सुसंगत है क्योकि यह पत्रो से सम्बन्धित है और इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूगा कि क्या वे यह बताने का प्रयत्न करेंगे कि दोनों का कितना खर्च है।

दूसरी बात यह है कि मेरे पास आंकड़े हैं कि 20 ऐसे बड़े ग्रुप हैं जो सारे न्यूजप्रिंट्स का लगभग 60 प्रतिशत ले जाते हैं और बाकी जो छोटे छोटे पत्र हैं उन को इधर उधर से न्यूजप्रिंट लेना पड़ता है और ये बड़े मालिक ब्लैक में उस न्यूजप्रिंट को बेचते हैं। इस तरह से इस प्रकार के समाचार पत्र हैं जिन को काफ़ी न्यूजप्रिंट मिल जाता है और दूसरी तरफ़ छोट समाचार पत्रों को न्यूजप्रिंट नहीं मिलता है। इस प्रकार से न्यूजप्रिंट का दुरुपयोग हो रहा है और छोट पत्र साप्ताहिक या क्षेत्रीय समाचार पत्र अखबारी कागज के अभाव में भारी सकट में है।

एक बात और मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो कुछ प्रेस परिषद् के बारे में चला हुआ है और अभी यह जो अवधि बढ़ाई जा रही है, इस अवधि के अन्दर वह अपना कार्य समाप्त करें और अपनी रिपोर्ट दें और रिपोर्ट के बाद जो तंत्र बनाने जा रहे है, वह ऐसा तंत्र हो, जिस से पत्रों की स्वाधीनता बनी रहे और ठीक ढंग से जो जनता की आवाज बुलन्द करते हैं उन की आवाज को दबाया न जाये और उन के ऊपर सेंसर लगा कर उन की आवाज को दबाने का प्रयत्न न किया जाए।

प्रस के बारे मे प्रस परिषद् की जो सिफारिशें हैं या प्रेस परिषद् को जिस प्रकार से फक्शन करना चाहिए, उस के बारे मे मैं मंत्री जी से यह निवदन करना चाहूंगा कि यहां पर प्रेस के बारे मे दो तीन बार चर्चा हुई है और क्योंकि इस विधेयक का दायरा बहुत छोटा है, इसलिए मै लम्बे विवाद में नही जाना चाहता लेकिन मै पुन: इतना निवेदन करूंगा कि आप जो अध्यादेश के जरिये अवधि को बढ़ाने की बात करते है, यह ठीक नही है। सन् 1968 में संसद् सदस्यो की जो सलाहकार समिति बनी थी और उस ने जो अपनी रिपोर्ट 1968 में दी थी, उस के अनुसार आप ने कार्यवाही भी की थी और जैसा कि मैंने अभी आप से निवेदन किया है कि इस प्रेस परिषद् का जैसा कार्य होना चाहिए, वकिंग जर्नलिस्टों के साथ न्याय हो रहा है या नहीं, एडिटर्स ठीक काम कर रहे हैं, मैनेजमेंट किस प्रकार से काम कर रहा है, इस बारे में जो ध्यान देना चाहिए वह सरकार का अपना दायित्व है और उस पर उस को ध्यान देना चाहिए लेकिन सरकार इस सम्बन्ध में उस प्रकार से ध्यान नही दे रही है। सरकार केवल यह देखती है कि कौन से पत्र उसकी भाषा बोलने है और कौन से नहीं? इसी का यह कारण है कि पत्रों के बारे में तरह तरह की बातें चली हुई हैं और सर कार के पक्ष के जो पत्र है, व ज्यादा लाभान्वित नही हो रहे है और सरकार के विपक्ष के जो अखबार है या सरकार की जो आलोचना करते है, उन पत्रों को बडी परेशानी उठानी पडती है। इसलिए मेरा कहना यह है कि चाहे सरकार की भाषा पत्र न बोल रहे हों लेकिन अगर वे किसी प्रकार से देश के अन्दर जनता की भावना को ले कर चलते हों, तो सरकार को उस आलोचना को स्वीकार करना चाहिए। आज सरकार रेडियो के जरिए से अपनी भाषा को बुलवाती है, जैसा चाहे प्रचार करती है। अभी जो काड इलाहाबाद मे हुआ, वह सरकारी भाषा में बोला गया लेकिन जो विपक्षवाले बात करते है या जो विपक्ष के सदस्य यहा पर बातें रखते या बोलते है, उन का प्रचार नही होता है। यह सरकार चाहे वह प्रेस हो, चाहे वह रेडियो हो या दूसरे माध्यम हो, सारे तंत्र अपने प्रचार के लिए प्रयोग में लाना चाहती है जैसा कि प्रेस परिषद् के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि प्रारम्भ मे यह कहा गया था :

"To build up a code of conduct for newspapers, news agencies and journalists in accordance with their high professional standards.

To ensure on the point of newspapers, news agencies and journal-

[डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय]

ists the maintenance of a high stanward of public taste".

इस के बारे मे आप ने कब कब ध्यान दिया, कब कब आपने इस के बारे में विचार किया कि आखिर जनता का कुछ रूचि होता है जनता की कुछ माग होती है, जैसे कि आकाशवाणी के बारे मे माग थी कि उसको कार्पोरेशन में बदल दिया जाए, उस को निगम में आप बदलिये, लेकिन आप उस पर विचार नहीं कर रहे है, आप उस के लिए चिंतित नही हैं आप उस को इसलिए नही करते है क्योंकि अप्रत्यक्ष रूप मे उस पर आप कब्ज किये हुए है और अगर आप उस को कार्पोरेशन में बदल देंगे, तो आप का कब्जा चला जाएगा और वह जनता की भाषा बोलने लगेगा । रेडियो को जनवाणी बनाइये, सरकारी प्रचार का यंत्र न बनाईये ।

तो मेरा कहना यह है कि सरकार का यह दायित्व है कि जो भी रास्ते इस्तेमाल हो सकते है पत्रों के जरिए, आकाशवाणी के जरिए और भी जो प्रचार माध्यम है उन के जरिए, हमारे देश के अन्दर इस प्रकार के उत्तरदायित्व की भावना का प्रादुर्भाव करें, पैदा करें जिस के कारण देश की जनता के अन्दर देश के प्रति एक निष्ठा पैदा हो और एक उच्चस्तरीय कल्पना देश के अन्दर हो, देश को आगे बढाने की दिशा में, उन के अन्दर किस प्रकार साहस और प्रेरणा पैदा हो, लेकिन सरकार इस दिशा मे कोई प्रयत्न नहीं कर रही है । सरकार इस दिशा को भूल चुकी है और विपक्ष को भला बुरा कह कर आगे बढ़ना चाहती है ।

जैसा कि मैंने प्रारम्भ में कहा था कि इस प्रेस परिषद् वाले मामले को पहली बार नही बल्कि तीसरी बार सरकार अध्यादेश के द्वारा सामने लाई है और मैं चाहता हूं कि सरकार अध्यादेश लाने का कोई प्रयत्न आगे न करे और इस प्रकार का यदि प्रयत्न किया जाता है, तो मैं समझता हूं कि वह जनतंत्र के हित में नहीं होगा । यह कदम जनतंत्र को ज्यादा मजबूत करने वाला नहीं कहा जा सकता । प्रेस परिषद् के बारे में जो अध्यादेश निकला था 25-7-74 को, तो उस समय मंत्री महोदय ने एक वक्तव्य दिया था ।

"The present composition of the nominating Commitee was adopted at the suggestion of the Advisory Committee of M.Ps on the Press Council. It was, therefore, decided to consult Members of Parliament representing different shades of opinion in order to arrive at a consensus on the machinery that should be set up for the nomination of Chairman and Members of the Press Council before action is take to amend the Act."

मै पुन कुछ बाते दोहराना चाहता हू । मेरी समझ मे नही आता कि सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति इस के अन्दर हो, लोक सभा के अध्यक्ष और राज्य सभा के चेयरमैन इस मे हों और फिर भी आलोचना हो । मैं माननीय ससद् सदस्यो का अत्यन्त आदर करता हू लेकिन क्या माननीय सदस्य भी इस प्रकार की व्यवस्था को ठीक नही समझते है । यदि आप आलोचना से डर गये हो तो मैं समझता हू कि अगर ससद् सदस्यों की जो समिति आपने बनाई है, वह जो तय सोचेगी, उस की भी आलोचना हो सकती है और यदि फंक्शनिंग मे कही खामियां है, तो उस को ठीक करना चाहिए । आप ने समिति बनाई है और यदि समिति असमर्थ है, तो उस के कारण होंगे । उन कारणो को आप यहां नही लाए । अगर लोक सभा और राज्य सभा के सदस्यो की समिति अपनी रिपोर्ट नही दे सकी है, तो जहां तक मेरी जानकारी है, सरकार जानबूझ कर विलम्ब करवा रही है । समिति की कई मीटिंगे बुलाई हैं या बैठकें बुलाई हैं , तो रिपोर्ट को फाइनेलाइज करना चाहिए था । उस

को फाइनेलाइज क्यों नही किया जा रहा है और इस मे क्या कठिनाइया पैदा हो रही हैं ।

इन शब्दों के साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि मंत्री महोदय इस अवधि को आगे बढ़ाने का प्रयत्न न करे और जो बाते मैंने उठाई हैं उन का जवाब दे । प्रेस परिषद् एक स्वतन्त्र सस्था बन कर देश के पत्रकारिता जगत मे उस के हितो का सम्पादन करे । प्रेस परिषद् जनता की भावना की रक्षा करने मे समर्थ हो और उस की रक्षा करने के लिए अपने को किसी के हाथ का खिलौना न बनने दे । वह स्वतन्त्र रूप से काम करे सरकार का पत्रों के ऊपर किसी तरह का दवाब न रहे और निर्भीकता के साथ पत्र अपनी भाषा मे बोले और जन भावना का उच्चारण करने मे समर्थ हो सके । इन शब्दों के साथ मैने जो निरनुमोदन का प्रस्ताव रखा है, उस को पेश करता हू और माननेय सदस्यों से निवेदन करता हू कि भी वे इसका समर्थन करने की कृपा करे ।

MR. CHAIRMAN: Resolution moved:

"This House disapproves of the Press Council (Second Amendment) Ordinance, 1974 (Ordinance No. 14 of 1974) promulgated by the President on the 27th December, 1974."

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI I K. GUJRAL): Sir, my hon. friend has delivered a very able and learned address but with a wrong promise because he has not bothered to understand as to why we had been forced to issue an ordinance; we were trying to introduce a Bill in the last session and we were hoping that the work would be completed.

MR. CHAIRMAN: You may kindly move the Motion for consideration first. Both these may be discussed together. After that discussion you can reply.

SHRI I. K. GUJRAL: Sir, I beg to move*.

"That the Bill further to amend the Press Council Act, 1965, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration"

MR. CHAIRMAN: Motion moved:

"That the Bill further to amend the Press Council Act, 1965 as passed by Rajya Sabha be taken into consideration."

SHRI DINEN BHATTACHARYYA (Serampore): It is better if the Minister replies to the mover of the Statutory Resolution, that is Dr Pandeya, as to what are the intentions of the Government This particular amendment has been hanging for a long time Nobody knows whether it will be passed at all in this session Because this kind of doubt arises from the way in which the Government is dealing with these matters. Government is not at all very serious to bring up this amendment and to form a regular democratic Press Council independent of any pressure of the press barons or of the Governmental machinery. They speak of election only so far as it suits them. They will not allow election to be free and fair if they consider their candidate will not be elected in the election. This is what happened in 1972 in West Bengal. That is why there was rigging. There is a chance of the same practices being practised in the States, which are under President's rule The Press is the media through which the public opinion is focussed. For a long time the Government has been talking and talking of de-linking the press from the grip of the monopoly houses and so on. But what really happens? It is the Government which is building up these monopolists. Just as the Mover of the Resolution pointed out, it has been pointed out in this House several times, how the Government is using the radio media to propagate the opinion of the Government The opinion of opposition parties or any

*Moved with the recommendation of the President.

[Shri Dinen Bhattacharyya]

democratic opinion of the people do not get any place in any radio broadcasts.

So, I am doubtful whether Government is at all true to its own profession that it wants to protect the freedom of presses. What do they mean by the Freedom of the Press? In this House it has been discussed and our party representatives referred to the happenings in Jamshedpur. An offensive was taken against the Gujarat Journalist by the Government through the police. And, recently, in West Bengal, I have seen and Government also knows it because it was mentioned in this House, that a weekly published a statement given by a Congress Minister in the Assembly. That is, Bangladesh had published a statement by the Minister Shri Sunit Chattoraj who is no longer a Minister because, as per Wanchoo Commission's report and as dictated by Shri S. Ray, Chief Minister of West Bengal, he had to resign from the ministry. And, on the floor of the House, he brought very serious charges against the Chief Minister which, to our opinion, may not be fully true. But there are some truths in it. On the very day, the Chief Minister took strong exception to it. The stormtroopers of Congress party in power attacked the press, ransacked it. The owner of the press was assualted by these stormtroopers; *Darpana Patrika* is also a weekly paper. Frontier has also focussed the grievances of the ordinary people. Because that does not suit the Government and so they were also attacked. This way, in every State, this thing is going on. He mentioned just now about the Searchlight paper. Everybody knows that story. What was their fault? You may hold any opinion; the press must have a freedom to express its views. It is the people who are to judge what is right or what is wrong. Government is not to do that. But, that *Searchlight* was attacked; the press was burnt. Everybody knows by whom and why? Uptill now, it is still to be investigated by the Home Ministry who is the culprit. It is strange. The same thing is taking place in West Bengal also; there is no freedom of press. It is the practice of this Government that so long as it praises Shrimati Indira Gandhi and her Government, it is alright. As soon as it goes against them or propagates for the true principles of democratic life and what measures should be adopted by Government to really curb the monopoly of the landlords and to fight against the price rise etc., then those presses would be attacked and they will be put to all kinds of troubles. There are other ways of curbing the freedom of the press. The newsprint is under their control. They have said here that to the maximum upto one lakh publications, they will get the news print quota. But, may I ask the Minister as to whether the Govt. knows the actual publication of certain big papers and what quota they actually get from Government? I know that in some cases to the extent of four lakhs daily publications, they are getting the newsprint. You are controlling the press through distribution of newsprint quota and through giving advertisements to the papers also, you are purchasing almost all the papers.

17.00 hrs.

These papers seldom dare to bring forward the anti people actions of the Government. As soon as they do it they will be denied the advertisements and the newsprint. Those editors who will exercise their conscience and try to focus the grievances of the people and try to divulge the truth, the owners of those papers will be pressurised by the Government to see that those editors are chucked off from their editorship. It has taken place in West Bengal. No less a person than Shri Vivekananda Mukhopadhya had to leave a Congress paper now owned by the West Bengal Government, namely, *Basumati Patrika*, because he could not express his opinion

in the paper. Everybody knows about Mr. Verghese's case. Although it is a *sub judice* matter still I would say that it smacks of evil and pressurising tactics of the Government so far freedom of Press is concerned. They adopt all possible means to control the Press, radio and other mass meda.

The formation of Press Council could not be completed through three persons of very high position like Mr. Speaker, Chairman of Rajya Sabha and the Chief Justice of Supreme Court. They were to nominate them. Then a Committee was formed consisting of Members of both the Houses but it is still sagging in the air. I do not know when the work of that Committee will get completed. The Minister himself does not know because today he is a Minister and tomorrow he may not be there. If he chooses to say something straightforward he may lose his job. So, even Mr. Gujral does not know the fate of this Press Council.

Sir, the rule of Ordinances has become a regular feature of this Government. Even in the matter of formation of a Press Council they had to come forward with an Ordinance. This is a matter of shame on the part of Government.

I say that the Pess Council must be an organ through which not only the business circles or big industrialist are able to focus their viewpoint and for which learned persons like retired judges and big professors have to be placed in the Press Council but my suggestion is that all sections of the Press, namely, working journalists and small newspapers should be represented there. Today I saw a list of persons who have been given the charge of advising the Government for the distribution of newsprint. One does not find the name of any person representing a district level paper. Only names of persons controlling big papers in the cities are there.

In the districts and sub divisional towns, so many newspapers are published, but, they are not getting any encouragement from this Government although they speak of it. Therefore, my point is that journalists should be taken in, the representatives of press workers should be taken in, the small papers and the district papers should also be given representations and all corruption in regard to distribution of newsprint, giving advertisements and pressurising tactics of big press must be stopped and unless you do it, there is no meaning in setting up this Council. It will be a mere hoax. Nothing more than that. In the end, I again express my doubts whether the Government is sincere in this matter or not. The Minister must convince the House as to when and in what way they are going to form the Press Council.

श्री अनन्तराव पाटिल (खेड) : सभापति महोदय, डा० लक्ष्मी नारायण पांडे ने जो प्रस्ताव सदन के सामने रखा है मैं उसका विरोध करता हूं और मंत्री महोदय गुजराल साहब ने जो बिल पेश किया है, उसका मैं समर्थन करता हूं। पांडेजी और श्री दीनेन भट्टाचार्य ने जो प्रश्न उठाये हैं, उनका उत्तर मैं देना जानता हूं, तो भी इसका उत्तर मैं मंत्री महोदय पर सौंप देता हूं और मैं बिल के बारे में चन्द शब्दों में अपने विचार इस सदन के सामने रखना चाहता हूं।

It is a very simple Bill. It is only trying to extend....

सभापति महोदय : आप तो हिन्दी में बोल रहे थे ?

श्री अनन्तराव पाटिल : श्री पाडे हिंदी में बोल रहे थे इसलिए मैंने उनका जवाब हिन्दी में दिया।

सभापति महोदय : मुझे लगा कि शुरू में आप हिन्दी में बोलना चाहते हैं। इतना अच्छा आप हिन्दी मे बोलते है, हिन्दी में बोलिये।

श्री अनन्तराव पाटिल : मैं हिन्दी में बोल सकता हूं ।

It is only trying to extend the time limit of the Press Council, to the end of this year. We can call it a routine Bill. But, some of the Members might be interested in going through the various aspects of the Indian Press in this country. Sir, as you know, a Parliamentary Committee has been formed, consisting of Members from both the Houses, and it has been working on drafting a Bill for constituting the new Press Council. It would not be proper for me to go into the merits or demerits of the proposed Bill because I happen to be a Member of that Committee. But, Sir, I would like to comment on the functioning and constitution of the Press Council. Now...

SHRI S. M. BANERJEE (Kanpur): As a member, he should not speak.

SHRI ANANTRAO PATIL: I am not criticising. The House must know how does the Press Council function, whether it is useful and whether it is beneficial or not, because, adverse comments have been offered by both the Members on the Press Council. Therefore, I must speak on that. This Press Council was created or constituted by drafting a Bill in 1965. It means nine years have passed. If you want to make an assessment of the working ed by drafting a Bill in 1965. It means not be out of place. It would not be doing any injustice to the Press Council. Sir, the main aim and object of the Press Council is to preserve the freedom of the Press. The second aim is to maintain and to improve the standards of the Indian journals and the journalists. This Press Council came into existence on the recommendation of the Press Commission. The Press Commission had recommended that in this country, a Press Council is a necessity to maintain and to improve the standards of the Indian journals

There is a difference between our Press Council in India and the Press Council in other countries. Our Council is created by an Act of Parliament. A Bill was brought forward and we gave them the machinery, how the Council is to be constituted, what type of functions it is expected to discharge. Some members are under the wrong impression that Government has got direct control or direct link with the Press Council, which is not a fact. It is a statutory, autonomous, free body. It has nothing to do with the Government

SHRI M. C. DAGA (Pali): Who nominees the Chairman of the Council?

SHRI ANANTRAO PATIL: I am going to tell you everything.

During the last 9 years of its functioning, there may have been some acts of omission and commission on the part of the Council, but by and large, it has done its best to fulfil the objectives for which it was created No doubt, there are some shortcomings, because the Council was not armed with sufficient powers. Let us take the case of the Haryana Government. When a case came before the Council relating to that Government, the State Government said: 'We do not recognise the Press Council'. Now another important case is going on before the Press Council as well as before the Delhi High Court, that is, the case of Mr Verghese, Editor of *Hindustan Times* Here again, the proprietors of *Hindustan Times*, their counsel, has claimed or pleaded that the Press Council has no jurisdiction, that it cannot deal with the case of Mr. Verghese.

I am pointing out that these are the weaknesses because the Press Council is not sufficiently armed with powers.

SHRI B. V. NAIK (Kanara): As a member of the Press Council, you are bound to defend it.

SHRI ANANTRAO PATIL: A question was asked about who nominates the Chairman. The Bill itself contains a provision how the Council will be

constituted, who will be the nominating committee, who will be the members. There was a nominating committee consisting of the Speaker of Lok Sabha, the Chairman of Rajya Sabha and the Chief Justice of the Supreme Court. The members were selected from different bodies, from proprietors, from working journalists, from the management and from other sources also.

SHRI M. C. DAGA: What are those other sources?

SHRI ANANTRAO PATIL: Commoners, representatives of laymen.

When criticism appeared in some newspapers about the nomination or selection of members, these three high dignitaries of the nominating Committee declined to serve as a nominating body and a crisis developed. So Government thought it fit to come again to Parliament for the constitution of a new Press Council. This could not be done during the stipulated time and so an ordinance had to be promulgated. I hope the Minister will find it possible to bring the new Bill during this session, and it will try to do away with the shortcoming which the present Press Council is facing.

Besides maintaining and improving the standard of journalism, the other function of the Council, which is very important, is that any citizen, newspaperman, editor, working journalist or a reader of a newspaper can bring to the notice of the Council or allege in the form of a complaint that such and such journal is not functioning according to journalistic standards, or such and such newspaper is printing obscene matter. Such cases came up to the Press Council and the Council was good enough to deal with them. There was no legal sanction; there was only moral sanction. Some journals which used to plead guilty were censured. The question is whether in future censure is an adequate corrective measure. When we say that the Press Council has to maintain and preserve journalistic standard or improve it, is it possible when monopolistic and restrictive trade practices exist in relation to jornalistic sphere and the Government do not propose to take steps immediately.

SHRI M. C. DAGA: What is journalistic standard?

MR. CHAIRMAN: May I request him to reserve his questions to the Minister?

SHRI M. C. DAGA: He is a great journalist.

SHRI ANANTRAO PATIL: Of 30 years standing. Journalist standard is difficult to define in one sentence. I shall tell you some examples.

MR. CHAIRMAN: You can do it later, you can hold a seminar and educate him. Please complete your speech here.

SHRI B. V. NAIK. Loyalty to truth is the journalistic standard.

MR. CHAIRMAN: Mr. Naik will have his chance.

SHRI ANANTRAO PATIL: We would expect from the Government that the big Press should have been delinked and diffused long time back. Otherwise, journalistic standards are not going to improve. During the last six months or even one year, what is going on in the newspaper world? Newspapers should educate people, and create an informed public opinion to save democracy and have peace and non-violence in the country. During the last few months many big newspapers belonging to big monopoly houses are directly indulging in politics and creating such an atmosphere that sometimes we are made to think whether democracy is in peril? Speaking in a gathering of journalists on the freedom of the Press in India and in Asia, the President of the International Press Institute Mr. Meir said: "Political pressures by ruling parties in Asia were the biggest threat to the

Disapp. of Press Council (2nd Amdt.) Ord., 1974 & Bill

[Shri Anantrao Patil]

freedom of the Press. India, Malaysia and Indonesia and Phillippines until recently had a free Press but now the Governments in these countries had invaded the Free Press or demolished this freedom." This is totally incorrect. I say so not because I belong to that profession or I belong to the Ruling Party. With my experience of the last six years in the Press Council I say that I do not think there is any infringement of freedom of the Press by the State or by the Government. I have myself criticised and I have been criticising the Congress Government at the State and at the Centre and nobody has asked me: though you belong to the Congress Party, why do you criticise the Government?

This is what I call freedom of the Press, freedom of the editor. But freedom of the Press and freedom of the editor do not mean licence. These big newspapers and their proprietors, managements and Boards of Directors think that freedom of the Press means licence.

You take the *Indian Express* and their allied publications in Indian languages. They have started a crusade against the Government, against the ruling party. I do not want to go into a controversy about "Motherland" or other papers and what they are indulging in. But the first and foremost duty of the newspapers of this country at this juncture is not only to save freedom but to strengthen freedom and democracy and see that this country progresses.

How many newspapers in the metropolitan cities do take cognizance of the problems and the worries of the common man far away from the big cities? Recently a Fact-finding Committee has given its report. It has not been made available to Members of Parliament. It is a monumental document and I pay my compliments to the Members and Chairman of that Committee. In that Committee's Report it has been stated that the newspaper business creates or generates wealth and gets more profit than any other business. They have given examples. But I would like to know how many of these papers plough back their money or profit to improve the standard of their journals or journalism in India, whether their profits are ploughed back into the language newspapers so that their standard also improves. It has not been done. So, at this juncture what is required is this. Government has also admitted it and they were only waiting for this Committee's Report. The first thing which we have to do is to de-link the press from the big business houses. If we do not do that, I think all the recommendations of the various bodies like the Press Commission, the Diwakar Committee and this Fact-finding Committee will be of no use. If the present tendency continues, the big papers with their monopolistic tendencies and restrictive practices will never allow small and medium newspapers to grow.

The Press Commission had stated in their report that newspapers were meant to give news. But todays newspapers are meant to give advertisements. If you see the *Hindustan Times* or any other newspaper, you will find that 75 per cent of the space is consumed by advertisements and only 25 per cent by news. We are spending crores of dollars and other valuable foreign exchange for importing newsprint and all this is unnecessarily wasted for printing advertisements. So, this Fact-finding Committee has recommended that if the ratio of 60-40 cannot be maintained, at least a ratio of 50-50 should be maintained and that it should be made compulsory.

When the big newspapers get a revenue of Rs. 1 crore or Rs. 2 crores, why should there not be a tax on advertisements? On the contrary our Finance Minister has levied a tax of one per cent on all production which includes newspapers also. Today taking the cost of production of newspapers, it is a battle for survival for

the small and medium newspapers and, therefore, I would urge upon the Minister to request the Finance Minister that this tax should not be levied on the small and medium newspapers.

Finally, the Press Council which will come into existence after the passing of the proposed Bill should be sufficiently armed with powers and we should not be satisfied merely with moral sanction. I have already said that I pay my compliments to the Chairman and members of the Press Council. They did their best. I hope the next Press Council's Chairman and members will also do their best.

With these words, I support the Bill.

SHRI S. M. BANERJEE: Sir, this particular Bill was passed by Rajya Sabha and the minister replied to some of the points raised there. When we talk of the freedom of the Press, we should try to define what should be the freedom. I am all for the freedom of the press, but freedom for what? If some of the press magnates whom we call vested interests or monopolists, to protect their own interests whether in the jute industry or textile industry or iron and steel or even the interests of the Government, utilise the press for that purpose, that particular freedom should be checked.

My hon. friend, Shri Anantrao Patil, is an outstanding journalist and I have great regard for him. But when a decision was almost tentatively taken to bring a Bill about future press ownership, is it not a fact that the Chairman of the Press Council, Justice Rajagopala Aiyangar, had a talk with Mr. K. K. Birla and wanted to advise him to convent the *Hindustan Times* and other papers into a trust to avoid diffusion of press ownership, so as to enable the Government to introduce this legislation? I want a satisfactory reply to this question. If it is true, he has done the greatest harm to our country and I don't feel that he should continue any more as Chairman of the Press Council.

As I said, I am all for the freedom of the press, but the manner in which certain news are twisted, distorted and magnified is a matter to be seen and understood. The case of the editor of *Hindustan Times*, Mr. George Vergese has been referred to many times that he has been victimised by Shri Birla and they say that Government had some hand in it. All newspapers have come out with editorials defending Mr. Verghese, as if to defend Mr. Verghese is to defend the freedom of the Press. Where was the freedom of the press gone, where were the champions of the freedom of the press, when Shri B. R. Vatts, one of the finest journalists, a correspondent of the PTI, was victimised by the PTI authorities? Not a word in support of his claims came except from those who were sincere journalists, who owe their allegiance only to journalism. All the trade unions stood by the side of Shri Vatts. But, as far as my information goes, Shri Verghese never tried to champion the cause of those working journalists who are really workers. So, I do not want to say anything about his case. Let him fight with the Government or the Birlas, as he likes.

Then I come to the horrible conditions of the working and non-working journalists in some of the newspapers. Recently when I was in Bangalore and I was addressing a press conference some of the journalists told me what they are getting at present. While every industrial employee in the country has got some interim relief, the journalists were denied even interim relief. Some of these journalists were getting 50 paise as mileage allowance for their rounds. I am surprised that this is the condition of the journalists even today when the newspapers are making fabulous profits.

Coming to the small newspapers, which are neither favoured by the Government nor by the big business houses, they are honestly trying to run their papers in a balanced way and not to satisfy somebody. But they find that they are unable to pay their journalists. There are instances where the

[Shri S. M. Banerjee.]

journalist do not get their salaries for months together. They carry on with some advances which they get. I would like to know what is the policy of Government regarding small newspapers.

Then I come to the conversion of PTI and Samachar Bharati into a public corporation. A solemn promise was made in this House, on the basis of the Press Commission Report which was published long ago, that PTI would be converted into a public corporation. What has happened to that promise? I say as the president of the PTI Employees' Union that this is our demand and that we shall continue to agitate as long as it is not converted into a public corporation.

The PTI has constructed a huge building in Parliament Street for which lakhs of rupees have been advanced by Government and financial institutions. I do not know what is the earning out of that building. When we talk of acceding to the demands of the workers, the General Manager comes with a weeping face and says that it is with the greatest difficulty that he is paying the wages of the employees and, perhaps, after his tenure is over they will not get even their wages. This is a sad commentary on the working of the PTI. Now the PTI is headed by whom? It is headed by the same business people, who are the directors of the PTI and UNI. I say that those directors should be removed and both PTI and UNI should be converted into public corporations.

Then, what has happened to the Bill on diffusion of ownership of the press? They were saying that they were awaiting the report of the Commission. The greatest tragedy in this country is that tired or retired judges of the Supreme Court or High Court are appointed as commissions, and they never submit their report, because submission of the report means unemployment for them. I would like to know from Shri Gujral whether he is really interested in breaking the monopoly in the press, or he is also going to succumb to the pressure of the big business houses.

I have come to know that the Press Council has given some patronage to the puppet organisation of the so-called journalists, the National Union of Journalists, that is the N.U.J. I do not know whether the N.U.J. really represent even 10 per cent of the journalists. In 1974, the verification was done in their case, under the Code, and the membership of the Federation of Journalists which is the only organisation of the working journalists who are bold, honest and men of integrity, out of 3,000 journalists, was 2,700 and odd. The membership of the N.U.J. was not verified because they did not cooperate with the verification.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE (Gwalior): The hon. Member does not know that it was the Press Council which carried out the verification in regard to the membership of the N.U.J. and they gave recognition He does not know what he is talking about.

SHRI S. M. BANERJEE: I am speaking about the Labour Minister's statement.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE Now, we see the link. We understand the link with the Labour Minister

SHRI S. M. BANERJEE: I am not concerned with the *Link* or *Patriot* or *Motherland*.

I am talking about the Labour Minister's statement: The Labour Ministry conducted the verification for the purposes of granting representation to them in the Wage Board. When they claimed that they have got so many members, naturally, the usual way is to carry out verification under the Code of discipline which has been accepted by all journalists and the workers who come under the definition of "workers". The verification

was done and they could not secure even 200 members. They have big leaders, whether it is my hon. friend, Shri Atal Bihari Vajpayee or Shri Shyamnandan Mishra, one of the tallest men in the House. I do not know. But it is true that they could not secure even 200 members.

I would request Shri Gujral, if the Labour Minister did not succumb to the bullying and pressurising tactics of the N.U.J., not to fall a prey in the hands of the N.U.J. This is neither national nor union nor journalists. Therefore, I would urge upon the hon. Minister, Shri Gujral, to see that every opportunity is given to working journalists. How the word "news" came to be formed? North-east, west and south forms the word "news", That is how the word "news" was formed.

सभापति महोदय : समाचार का भी ऐसा ही कोई मतलब निकालिए।

श्री एस० एम० बनर्जी : इसी लिए मुझे यह कहना पड़ेगा कि प्रेस को आजादी जरूर होनी चाहिए, लेकिन ऐसी आजादी न हो जैसे देश में फुटपाथ पर कोई लेटा हुआ जाड़े में ठिठुर कर मर जाय और किसी की हिम्मत न हो कि पूछ ले—क्यों मर रहा है। ऐसी आजादी प्रेस की नही होनी चाहिए। वे जिस तरह से चाहे करें, लेकिन उन को देश के बनाने में मदद करनी पड़ेगी, सरकार की भ्रष्ट पालिसी को खत्म करने मे मदद करनी पड़ेगी। जबा अवाम की जरूरत की चीजो को हासिल कराने मे प्रेस अगर मदद न करे तो वैसी आजादी नही होनी चाहिए।

श्री शंकर दयाल सिंह (चतरा) : सभापति जी, प्रेस परिषद् के सम्बन्ध में अभी हम जो चर्चा कर रहे हैं इस का केन्द्र बिन्दु समाचार-पत्रों की स्वाधीनता, सरकार की नीति और राजनीति से उन के जो ताल्लुकात है, ये सारी बातें इस में आ रही हैं। मै इन में बहुत विस्तार में न जा कर, संक्षेप मे ही अपनी बातें कहना चाहूंगा। लेकिन इस के पहले एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा—दुनिया के कई हिस्सों मे मुझे भी जाने का मौका मिला, समाचार पत्रों को देखने और पढ़ने का मुझ भी मौका मिलता रहा है।

आज भारत के समाचार-पत्रों को जितनी स्वाधीनता मिली है उतनी शायद दुनिया के किसी कोने में पत्रों को नहीं मिली है। और कोई बात अगर कही जाय सम्भव है कि उस की कोई महमति हो सकती है, लेकिन जहां तक समाचार-पत्रों की नीतियों तथा स्वायतता के सम्बन्ध में बात आती है हम स्वयं देखते हैं कि जो समाचार-पत्र सदा सरकारी विज्ञापन के सहारे चलते हैं फिर भी सरकार को ही उन के द्वारा गालियां सुननी पड़ती है ऐसा दुनिया मे शायद ही कही होता हो।

अभी सरकार के सामने जो फैक्ट फ़ाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट आयी है उस पर सरकार को अपने को केन्द्रित करना चाहिए और जो सिफारिशे दी है सदस्यों की कमेटी ने उन को लागू करने की और सरकार को कदम बढ़ाना चाहिए। दो, चार बाते ऐसी है जिन मे कोई विरोध हो सकता। खुद उस कमेटी की रिपोर्ट मे यह कहा गया कि "लोकतंत्रीय व्यवस्था मे समाचार-पत्रों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है और जनसपर्क के इस माध्यम की क्षमता के विकास की दृष्टि से यह अनिवार्य है कि इस मे एकाधिकार न बढ़ने दिया जाय।" इसलिए जो सब से बड़ा प्रश्न है एकाधिकार की प्रवृत्ति का उस को बन्द कर। एक एक पत्र ऐसे है कि जितना कागज हम अखबारी कोटे मे देते है उस का बहुत बड़ा प्रतिशत वे हजम कर जाते है और उन कागजों का दुरुपयोग भी होता है। ब्लैक मार्केट मे बिकता है, कुछ गाली देने में काम आता है और कुछ स्याही की पूर्ति में बेकार खर्च होता है। और उसी समिति ने अपनी रिपोर्ट में यह कहा है कि जो विज्ञापन

[श्री शकर दयाल सिंह]

छापे जाते है और जो समाचार हैं उन का रेशियो होना चाहिए। माननीय पाटिल ने कहा कि 50, 50 प्रतिशत इन कामो के लिए निर्धारित होना चाहिए। मेरी राय मे यह अन्याय है। 60 प्रतिशत समाचारो के लिए होना चाहिए और 40 प्रतिशत विज्ञापनो के लिए। क्योकि सामान्य जनता पर इस का बहुत बडा भार पडता है। जितने भी अखबार हैं चाहे दैनिक हो, मासिक हो, या साप्ताहिक हो, उन सब के मूल्य एक साल मे दुगने हो गये हैं। जो कम आय वाली जनता है उन का भी सम्बन्ध अखबारो से उसी तरह है जैसे सुबह सुबह चाय के साथ हुआ करता है। तो इस भार को सरकार को देखना चाहिए और इसीलिए जो समिति बनायी थी मूल्य नियत्रण की सिफारिश ही उस का मुख्य उद्देश्य था और उसने कहा है कि

> "कराधान ब्याज और लाभाश अलग अलग करने के पूर्व जिन 115 दैनिक पत्रो की छानबीन की गई उन के मुनाफे का औसत 11 प्रतिशत 4 प्रतिशत था और पूजी के अनुपात मे यह लाभ 29 6 प्रतिशत था तथा 25 000 वर्ग सेंटीमीटर के समाचार-पत्र का मुनाफा 3.3 पैसा था।'

तो इन चीजो को अपने सामने रखना होगा। साथ ही उस सिफारिश मे यह भी कहा गया है :

> "सूचना तथा प्रसारण मत्रालय के अन्तर्गत एक ऐसा सगठन बनाया जाय जो उसे समाचार-पत्रो के मूल्य तथा विज्ञापन की दर के बारे मे सलाह दिया करे।"

अब मैं इस सम्बन्ध में एक सुझाव सरकार को देना चाहूगा कि जो अलग अलग कमेटियां आपने बना दी हैं उन को केन्द्रित करे। प्रेस काउन्सिल आप की है तो फिर अखबारी कागज बाटने के लिए दूसरी अलग कमेटी और दूसरे कामो के लिए अलग कमेटी। इस का क्या औचित्य है? आप को सैन्ट्रलाइज करना चाहिए।

और सब से जरूरी बात यह है कि जो रिटायर्ड लोगो को आप चेयरमैन बना देते हैं यह नही होना चाहिए। क्योकि वह तो चाहते हैं कि उन की अवधि बढ़ती चली जाय। क्यो नही किसी पत्रकार को आप उस का चेयरमैन बनाते है? क्यो नही ऐसे व्यक्ति को बनाते है जो पाठक वर्ग का प्रतिनिधित्व करे? या किसी बौद्धिक वर्ग के प्रतिनिधि को क्यो नही आप चेयरमैन बनाते हैं?

मैं यह जानना चाहूगा कि प्रेस परिषद् से क्या क्या लाभ अभी तक हुए हैं? क्या कि हमे अभी तक इस बारे मे कुछ भी पता नही चल सका है केवल लीगल चीजो को छोड कर और कोई लाभ उस मे नही हुआ।

अभी जो भाषण दिये गये उन मे कहा गया कि सरकार द्वारा विज्ञापन बन्द कर दिये जाते है। बिहार सरकार ने जब "सर्च लाइट" और प्रदीप" का विज्ञापन बन्द किया था और प्रेस परिषद् ने जब उस के बारे मे निर्णय किया तो बिहार सरकार ने तत्काल उस को मान कर फिर से उसे विज्ञापन देना शुरू कर दिया।

एक बात मैं और कहना चाहता हू कि भाषायी-पत्रो पर अधिक से अधिक ध्यान देना चाहिए। अग्रेजी पत्रो को तो लाभ मिल जाता है लेकिन दूसरी भाषा के जो पत्र है जैसे तमिल के तेलगू के गुजराती के बगला के या हिन्दी के उन को उतना लाभ नही मिल पाता है। इसलिये भाषायी पत्रों को भी अनुपात से ज्यादा लाभ मिले इस की आप को व्यवस्था करनी चाहिए।

हमारे यहां जो न्यूज एजेन्सीज हैं उन को भी एक दृष्टि से देखें ताकि सब को बराबर लाभ मिले। अभी एक अखबार में समाचार आया कि इंडियन एयर लाइन्स ने 40 पत्रकारों को मुफ्त विमानों में यात्रा की सुविधा दी। मैं इस के खिलाफ हूं, आप 400 पत्रकारों को यह सुविधा दें। लेकिन केवल अंग्रेजी के पत्रकारों को यह सुविधा मिले और दूसरे भाषायी पत्रों के पत्रकारों को न मिले यह नहीं होना चाहिए। इसलिए जो दूसरी भाषायी न्यूज एजेन्सियां है जो कई भाषाओं के पत्र है उन को भी सुविधा मिलनी चाहिए और प्रेस परिषद् को सब के साथ न्यायपूर्ण तरीके से चलना चाहिए जिस से छोटे पत्रों को और श्रमजीवी पत्रकारों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचे।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। और सरकार से चाहूंगा कि वह व्यावहारिक कदम इस सम्बन्ध में उठाये।

MR. CHAIRMEN: Now, before I call the next speaker, only two hours are allotted for this and we have already taken 1 hour 45 minutes. We must finish this Bill as also there is another Bill. Unless you want to sit late, I would request the remaining members not to take more than five minutes each.

SHRI P G MAVALANKAR (Ahmedabad): It is only 1 hour and 15 minutes because we started at 4.30 p.m. It is not 1 hour 45 minutes that we have taken.

MR. CHAIRMAN: All right, the idea is that we have to finish it

श्री जनेश्वर मिश्र (इलाहाबाद): सभापति जी, ऐसे तो इस बिल का जो मकसद है वह बहुत ही छोटा है वर्तमान प्रेस काउन्सिल को थोड़ा सा और ज्यादा वक्त देना है। इतना ही मतलब है। लेकिन इस समय जिस तरह की चर्चायें चल रही हैं उन से ऐसा लग रहा है कि भारत की पत्रकारिता की आजादी को खतरा आ गया है। मुझे याद है कि जब रेडियो की चर्चा चल रही थी और श्री धारिया के बयान को तोडने की बात चल रही थी तो माननीय गुजराल ने कहा था कि जिस तरह बहुत से अखबारों के संवाद कार्यालय चलते है उसी तरह से रेडियो के भी चलते है। ऐसा लग रहा था कि समाचार-पत्रों के संवाद कार्यालय ठाक से नहीं चलते। जिस समय कश्मीर के समझौते के बारे में हम ने बात छेड़ी थी प्रधान मंत्री ने कि शेख अबदुल्ला ने महासभा के बारे में एक जगह बयान दिया है तो प्रधान मंत्री ने यही कहा था कि समाचार पत्र क्या छपते है इस पर हमें ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। इस से लगता है कि समाचार-पत्रों के बारे में क्या राय है। छोटे मियां छोटे मियां, बड़े मियां शुभानल्लाह। माननीय बरुआ साहब ने तो यहां तक कह दिया कि आज के समाचार-पत्र विरोधियों के ज्यादा समाचार छापते हैं और हम से कम। और कलकत्ता में उन्होंने कहा कि हमने लाखों की मीटिंग में भाषण दिया, उस को नहीं छापा और जय प्रकाश जी के छोटे से प्रदर्शन को खूब बढ़ा चढ़ा कर छापा।

तो उस से इन लोगों की नियत का पता लगता है कि ये लोग इस समय क्या चाहते है और उस के बाद कहते है कि जम्हूरियत की हिफाजत के लिए हिंसा को रोकने के लिए समाचार पत्रों को बहुत आजादी नहीं दी जा सकती कि वे जो चाहे छापते चले जाए। तो लगता है कि ये लोग आज समाचारपत्रों की आजादी पर कहीं न कहीं कुठाराघात करना चाहते हैं और इसके मकसद में लिखा हुआ है कि जिन तीन लोगों की कमेटी पहले बनाई गई हैं जिन्होंने प्रेस कौंसिल के मेम्बर को एपाइण्ट किया है, चैयरमैन वगैरह को एपाइन्ट किया है और उस में स्पीकर थे राज्य सभा के चेयरमैन

[श्री जनेश्वर मिश्र]

और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे इन जैसे लोगो पर भी शक होता था कि उन्होने किस तरह से एपाइण्ट किया और लोगो ने अपनी राय जाहिर की कि जो नियुक्ति की गई वह बहुत अच्छी नही थी, लेकिन अगर सही कहा जाए तो स्पीकर को सत्तारूढ दल चुनता है और उपराष्ट्रपति सत्तारूढ दल की मर्जी पर ही चुना जाता है जिस का बहुमत रहता है और ताकत रहती है। इसलिए यह शक किया जा रहा था कि पत्रकारिता के लिए कहा कोई खतरा है। इस के लिए एतराज क्यो है जब इन लोगो ने कहा कि हम इससे हट रहे है और आज जो यह डर है तो यह रास्ता बनाने जा रहे हैं। उस से बाद मे शक नही रहेगा। हिन्दुस्तान मे विचारो की आजादी के लिए अगर एक तरफ सत्तारूढ दल का पक्ष है तो दूसरी तरफ विरोधी पक्ष भी है और तीसरी तरफ पत्रकारो का भी सगठन होगा और उस का भी पक्ष है। तो किस्त ह से प्रेस कौसिल को नियुक्त किया जाए इस के लिए बार-बार इन तीनो को प्रतिनिधित्व दिया गया है और अगर नही दिया गया है तो जो कोई भी रिकमेडेशन आएगी और अगर पक्षपात होगा तो कोई भी उगली उठाएगा और फिर दो चार साल बाद आप कहेगे कि कोई उगली उठा रहा है और तब तक आप तानाशाह बन जाएगे और अगर आप कुर्सी पर बैठे रहेगे और इस देश की जनता ने आप को उखाडा नही तो फिर यह कहने लग जाएगे कि हिन्दुस्तान के समाचारपत्रो को भी 'प्रावदा' बना दिया जाए। इस बात का डर हो गया है सदर साहब।

श्री रामावतार शास्त्री : "प्रावदा" बन गया, तब तो खुशी की बात है।

श्री जनेश्वर मिश्र . इन का कहना है कि हिन्दुस्तान के सारे अखबार 'प्रावदा' बन जाएये, तो इन को खुशी होगी। अगर दिल्ली की पार्लियामेंट को दिल्ली से उठा कर मास्को मे बैठाने लगें, तो इन को ज्यादा खुशी होगी।

श्री रामावतार शास्त्री : तब नही होगी।

श्री जनेश्वर मिश्र जिस तरह से समाचारपत्रो के साथ, जो इस प्रकार सरकार के खिलाफ खबरें छापा करते हैं, यह सरकार एडवरटाइजमेंट्स, विज्ञापन देने मे मन मानी और बेईमानी करती है, उस की शिकायत यहा कई बार की जा चुकी है। ये लोग कब से कह रहे हैं कि 'मदरलैण्ड' अखबार 'इण्डियन एक्सप्रेस' लगातार सरकार के खिलाफ अनाप-शनाप छापते रहते हैं। सरकारी पक्ष के पक्ष मे जो अखबार छापते रहते हैं, उसकी शिकायत अगर हम करे तब क्या होगा।

सभापति जी, इतना ही इन लोगो ने नही किये है कि केवल विज्ञापन देने मे ही मन मानी बर्ती हो बल्कि कई दफा प्रधान मत्री औ गृह मत्री के यहा जो न्यूज टेलीप्रिंटर मशीन पर आती है और उन मे अगर कोई खबर ऐसी आ जाती है, जो इस सरकार के खिलाफ पडती है, तो ये एजेन्सियो के जरिए और मिनिस्ट्री के जरिए यह कहने हैं कि सेंसर करने की हमारी पावर है और इस को सेंसर कर दो। सेंसर का मतलब क्या है। अगर कोई वलगर न्यूज छपे, कोई गन्दी बात छपे जो नैतिकता से टकराती है, तो उस मे तो कुछ बात समझ मे आती है कि उस को सेंसर कर दिया जाए लेकिन प्रधान मत्री, मारुति सजय और सोनिया गाधी के बारे मे खबरे आने लगे, तो वह कैसे सेंसर हो सकता है। हिण्डालको कम्पनी, मिर्जापुर ने प्रधान मत्री के सचिवालय को 5 लाख रुपये दे दिया और वह इसलिए दे दिया कि आयन्दा हिण्डालको मे हडताल नही हो पाएगी। इस बात का आश्वासन सचिवालय ने दे दिया था और इन लोगो ने कोशिश की कि टेलिप्रिंट मे न्यूज न आए। यहां तक धांधलेबाजी की है।

इस तरफ़ गुजराल साहब को ध्यान देना चाहिए ।

बर्गिस के सवाल पर हमारे बनर्जी साहब कह कर चले गये । ऐसा लगता है कि पत्रकारों से जो लडाई चलती थी, उस मे उन के साथ वे नही रहे थे । इस तरह से अप्रत्यक्ष रूप से उन्होने एक तरह से बिडला साहब की मदद कर दी । कुछ मित्रो ने कहा है कि समाचार-पत्रो में एकाधिकार चल रहा है । कुछ लोगो ने एकाधिकार को समाप्त करने की बात कही यानी बिडला के एकाधिकार को समाप्त कर के और दूसरो के एकाधिकार को समाप्त कर के प्रधान मत्री श्रीमती इन्दिरा गाधी का, श्री ब्रह्मानन्द रेड्डी का और गुजराल साहब का एकाधिकार कायम कर दिया जाए। तो यहा पर मुल्क की आजाद भावना को व्यक्त करने के लिए कोई ऐजेन्सी नही रह जाएगी । जिस तरह से आज का रेडियो केवल प्रधान मत्री श्रीमती इन्दिरा गाधी और सत्तारूढ दल का प्रचार माध्यम बन गया है, ठीक उसी प्रकार से समाचारपत्रो की निर्भीकता को तोडने की अगर कोशिश की गई, तो यहा के समाचार-पत्र प्रावदा जैसे अखबार बन जाएगे । इस से शास्त्री जी की तबियत खुश हो जाएगी और मेरा ख्याल है कि गुजराल साहब भी इस को सुन कर खुश हो जाएगे लेकिन मुल्क का चरित्र और बल बहुत कमजोर हो जाएगा ।

मैं इतनी हिदायत दे कर अपनी बात खत्म करता हू ।

MR. CHAIRMAN: I would like to know from the Minister of Parliamentary Affairs how do we propose to go after six? It was first decided that at 6 O'clock, half-an-Hour discussion will be taken up

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI K. RAGHU RAMAIAH): The hon. Speaker said yesterday and he repeated it this morning that whatever time is spent on the earlier discussion under 193 we shall add after Six. I have consulted the leaders of several Opposition Members and we have now come to an agreement that today, we shall finish the Press Council (Amendment) Bill. After that, Half-an-Hour Discussion will be taken up.

Tomorrow, the House will sit until the Nagaland Proclamation, Nagaland Budget, Supplementary Demands for Grants and also the Air-Force and Army Laws Amending Bill and the Statutory Resolution regarding the Gujarat Electricity Board and all those items on the agenda papers are finished. So, tomorrow the House will sit as long as is necessary to finish those items That is the agreement which has been arrived at and I would request you to proceed with that accordingly

MR. CHAIRMAN: Should I take it that this is the view of the House? You say you have consulted already. And no body has objected to that. Anyway, formally, do you want me to put it? I shall put it formally. Is this proposal of the Minister for Parliamentary Affairs agreed to by the House?

SEVERAL HON MEMBERS: Yes, yes, it is agreed

MR. CHAIRMAN: Let Mr Naik now continue.

SHRI B. V. NAIK (Kanara): Mr. Chairman, Sir, I think this is the third time, that the Minister for information and Broadcasting, Shri I K. Gujral, has come forward here requesting for the extension of the time and coming up with certain concrete proposals. This is also, if I remember a right, the second time that an Ordinance has been invoked in order to extend the time of the Press Council. Last time also the same points were discussed and naturally from the essential point we discussed about the press at length.

[Shri B. V. Naik]

18.00 hrs.

The Minister of Information and Broadcasting from time to time tells us—whether it is a question of movie as the medium or the press as the medium—that the country has to make up its mind as to the ultimate pattern. He used the words whether the Press Council must have teeth or not have its teeth, in other words, whether it must have punitive and other powers or not. He said that the country has to make up its mind as to what sort of Press Council we must bring into this country. On my own part, I would say that before the country makes up its mind may we know whether the Minister has made up his mind or not? As a Minister it is his first duty to come up before the House and exactly tell us as to what his thinking is. Thereafter, it is for us to debate

It is the third time of extension for the Press Council. Let him make up his mind by the time he replies or let him accept my amendment regarding time-limit in making up the mind of the Government

The Press Council had been started in the year 1965 for maintaining standards of Indian journalism and for keeping the freedom of the Press. Have we succeeded in this limited object? I say, we have not. According to the report of the Press Council itself there is an Article which has appeared in Roopangana, a Gujarati weekly of Ahmedabad which I quote:

"Daughter of the traitor who did the maximum damage to the country is ruling today."

Obviously, it refers to the present Prime Minister and late Shri Jawahar Lal Nehru. What a pity! What did the Press Council do about it? The Press Council found it to be vulgar and utter lack of taste and admonished the Editor for it

I would like to have for maintenance of the freedom of the Press a person like Jack Anderson who revealed certain secrets. There is so much of complaint about some of our secret service agencies in this country. But, there has been no one like him to come out in the Press and bring out exactly a charge sheet about the secret service organisations or secret police or the CID or the CBI. Nor have we got the sort of political reporting of the standard of Waltar Lippman, late Lippman. Under the circumstances I am afraid I have no very flattering words to use about the Indian Press as it stands today, pressed on one side by black money and on the other side the insecurity which this big money breeds in the journals so that the best of the journals cannot find the light of the day. I would also like to know from the Minister, there was so much furore about *Prati Pakhsh* on the floor of this House. This may be a pre-dated report of the Press Council What has been the action taken either by the Government from the Centre or by the Press Council *suo moto* in regard to *Prati Pakhsh*? Mr Chairman, I am coming to the most relevant point Even when I am speaking today, I am not speaking for the Press gallery I wonder whether my figures could be wrong that 80 per cent of the people who are participating in the debates here are not speaking for the Press and for the effect of sensation including—since my dear friend Mr Shashi Bhushan agrees with me—members of the treasury benches and the Council of Ministers. Now, I ask a constable takes a rupee You call it corruption. In the vocabulary of the proponents of the total revolution, this is corruption I do not know whether playing to the Press gallery in the country, whether by the Ministers or the Members or other Members of the political fraternity is not intellectual corruption of the worst sort that we can find. that we do for the sake of effect. We create scenes on the floor of the House for the sake of effect and we create scenes so that our constituencies and the rest of them are fed on this abnormal behaviour of fairly normal and sane persons when we meet them in the Central

Hall. I think something has got to be done. Mr. Inder Gujral should no longer continue to sit on the fence. Then, he will have the fate of the Humpty Dumpty.

We know that the Press Council is a voluntary body in the UK. But, in India, we are spending Rs. 3,90,000. I do not mean to say that it can be bought for such a cheap price. the Press Council Budget. But, when the conditions are Indian, when Indian realities prevail, try to find out an Indian solution and don't go by hypothetical concepts of the freedom of the Press. Where is your freedom of the Press when the journalists are bought from head to foot with the rupees, annas and pies, indulging in blackmail and indulging in black-out? I am quite sure some of the very salient points will be blacked out by the Press. At the back of everything is the black money of the big business.

We talk in the air about obscenity. Something, very very innocent, of Kushwant Singh's writing, something out of his liberalism, is called as obscenity in our Press.

श्री राम सहाय पांडे (राजनंदगाव) : इनको आप मुझ पर छोड़ दीजिये। इनको मैं पूछने वाला हूं।

SHRI B. V. NAIK: Sir, as far as obscenity is concerned, what are these advertisements of various textile mills? I think the hon. Minister knows fully well. These photographic models, these photographic models, what are they? I do not want to go into the details about the whole racket of advertisements, advertisement and sales executives, models and photographers because this is International Women's Year I would only say that let us stop obscenity particularly within those affluent sections and the way of life that they are following. Therefore, Sir, I would urge this. I am coming to my last point. There are only three or four people in the country who are above criticism. There is the Speaker of the House, whose Chair you are adorning at present, there is the Vice-President and then the Chief Justice of India. Of course, the President of India is there in Rashtrapati Bhavan. These are the only people who are above criticism. We cannot bring in their names. Who else have we got to adorn this nominating committe? If they say that because of the criticism made, they are going to abdicate their responsibility, it would be an abdication of a very high responsibility cast on them by Parliament and the Act. I would therefore, say that they should not shirk their responsibility and the nominating committee should continue as before. Let the Minister accept my amendment.

[illegible]

18.11 hrs.

PAPER LAID ON THE TABLE—contd.

ORDER UNDER DELHI MUNICIPAL CORPORATION ACT, 1957

MR. CHAIRMAN: The hon. Minister of Home Affairs has requested that he be permitted to lay a paper on the Table of the House.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE (Gwalior): What paper?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI K. BRAHMANANDA REDDY): I seek permission to lay on the Table an Order under sub-section (1) of section 490 of the Delhi Municipal Corporation Act 1957 dated 24 March, 1975, along with a statement of the reasons as required under sub-section (3) of section 490 of the said Act. [*Placed in Library. See* No LT-9278/75].

MR. CHAIRMAN: The Speaker has given him to permission to lay it on the Table.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: सभापति जी, मेम्बरों को पता तो लगना चाहिए कि आपने कारपोरेशन को क्यों खत्म कर दिया